(b) whether there is a problem of interpretation of data available and collected by the CWC in accurately predicting potential flood-prone areas;

(c) whether it is a fact that large sums of money have been invested in Central Water Commission to fulfill the function of precise prediction and cautioning of public on potential floods; and

(d) steps being taken *to* revamp the whole organisation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (d) No, Sir. Central Water Com mission had b-en making timely forecasts and accurate flood warning to the public. The annual expenditure during VII Plan was about Rs. 10 crores only and this is not considered large for this purpose.

गुजरात में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनायें

4660. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बहुत सी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनायें विलंबकारी और अत्यधिक लागतों सिद्ध हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यरत निर्माणाधीन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को परियोजना-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) गुजरात सरकार को दी जाने वाली प्रस्तावित विशेष सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है और इस संबंध में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) नौ वृहद परियोजनाओं नामशः दमनगंगा, पानम, साबरमती, करजन, सुखी, सिपु, वतरक, सरदार सरोवर और जलखरी और पच्चीस मध्यम परियोजनाओं नामशः हिरन (एस)--II मुखबहादर मच्छुन्दरी, कालूमार, मच्छानाला, वेर--II, देव केलिया, हरनाव-II सानी, आमीपुर, उमरिया, आजी--II, (गुणातीत सरोवर) और बारह विस्तार, नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं नामशः मच्छु--I (बांध को सुदृढ़ करना), मच्छु--II (पुनर्निर्माण) खारोघट नहरों का आधुनिकीकरण, फतेहवादी नहरों का आधुनिकीकरण, दांतीवाड़ा आधुनिकीकरण, भादर, (एस) नहरों का आधुनिकीकरण, शतरूंजी (पी) नहरों का आधुनिकीकरण मच्छु--I नहरों का आधुनिकीकरण, लवणीयता अन्तः प्रवेश की रोकथाम (सौराष्ट्र समुद्र तट विकास) उकई-कंकरपार आधुनिकीकरण, मिट्टी और कलिंदी को बहाल करने की योजनाओं को आठवीं योजना में लाया गया है। परियोजनाओं को पूरा करने में हुये विलंब और इसके फलस्वरूप लागत में वृद्धि होने के कारण ये हैं:-

अपर्याप्त निधियों का प्रावधान, डिजाइन और कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन, निर्माण के दौरान सामने आने वाली तकनीकी और ठेके से संबंधित समस्यायें, परियोजना तैयार करते समय किया गया अपर्याप्त सर्वेक्षण आदि। चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिये कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती, लेकिन, योजना आयोग ने गुजरात को वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते आठवीं योजना के लिये 3426 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया है। आठवीं योजना में समयबद्ध ढंग से चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है।